web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 12 सितंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 343

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू में नहर में गिरी गाड़ी, तीन लोगों की मौत और एक नवजात लापता

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू के बाहरी इलाके पर बनी नहर में शनिवार को एक निजी कार गिर जाने के बाद दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक लापता शिशु की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाहन में सवार चार अन्य लोगों को बचा लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि यह हादसा तड़के मीरान साहिब में मरलियान में हुआ जब एक कार अर्निया में बहादरपुर गांव जाते हुए सड़क से फिसलकर नहर में जा गिरी। कार में आठ रिश्तेदार सवार थे। अधिकारी ने बताया कि गणेश कुमार गाड़ी चला रहे थे और एक मोड़ पर उन्होंने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। साथ ही बताया पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तत्काल बचाव अभियान चलाया। उन्होंने कुमार, उनकी पत्नी कंचन, मीनू कुमारी और उनके बेटे सुशांत को बचा लिया जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया कि बचावकर्मियों ने केवल कृष्ण (60), उनकी पत्नी सुरजीत कुमारी (52) और दो साल की मांशी का शव निकाला जबकि दो महीने की बच्ची प्रांशी की तलाश जारी है।

दाखिल खारिज से स्वामित्व का हक नहीं बनता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दाखिल खारिज (म्यूटेशन प्रविष्टि) से किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं मिलता है। यह केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। किसी संपत्ति के दाखिल का अर्थ स्थानीय नगर निगम या तहसील प्रशासन के राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व का हस्तांतरण या परिवर्तन है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस पर भी विवाद नहीं हो सकता कि वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। कानून की प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार, म्यूटेशन प्रविष्टि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं देती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष स्वामित्व या अधिकार का दावा कर रहा है, उसे उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। न्यायालय ने कहा कि आवेदक के अधिकारों को केवल सक्षम दीवानी अदालत के जरिये ही हासिल किया जा सकता है। अदालत के निर्णय के आधार पर जरूरी म्यूटेशन प्रविष्टि की जा सकती है। न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति के म्यूटेशन से न तो संपत्ति का स्वामित्व बनता है, न ही खत्म होता है। इस तरह की प्रविष्टियां केवल भू-राजस्व हासिल करने के लिए प्रासंगिक हैं। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने रीवा मंडल के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की मांग की थी।

जिला खनिज फाउंडेशन को मिली आयकर से छूट

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 165 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों (डीएमएफ) को आयकर भुगतान से छूट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। 2015 में, खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम संशोधन के माध्यम से, भारत सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तरीके से काम करना है। अभी तक, देश के 22 राज्यों के 600 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए गए हैं जिन्होंने डीएमएफ नियम बनाए हैं। जोशी ने केंद्रीय वित्त मंत्री मती निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा कल इस आशय की एक गजट अधिसूचना जारी की गई है।

न्याय पाने के लिए गरीबों के संघर्ष को मैंने बहुत निकटता से देखा है : राष्ट्रपति कोविंद

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि अगर हमें हमारे संविधान के समावेशी आदर्शों को अर्जित करना है, तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता है। वह आज (11 सितंबर, 2021) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।

राष्ट्रपति ने 1921 में भारत की पहली महिला वकील, सु कॉर्नेलिया सोराबजी को नामांकित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए, उस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ न्यायपालिका में महिलाओं की सहभागिता का एक नया इतिहास रचा गया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में से चार महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों ने भविष्य में देश में एक महिला मुख्य न्यायाधीश का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तव में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी। कोविंद ने कहा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर महिला

न्यायाधीशों की संख्या 12 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को हासिल करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने न्याय पाने के लिए गरीबों के संघर्ष को बहुत निकट से देखा है। न्यायपालिका से सभी को उम्मीदें हैं, फिर भी आमतौर पर लोग अदालतों की मदद लेने से हिचकिचाते हैं। न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को और बढ़ाने के लिए इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। यह हम सभी का उत्तरदायित्व है कि समय पर न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, निर्णय आम आदमी की समझ में आने वाली भाषा में हो, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को न्यायिक प्रक्रिया में न्याय मिले। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब न्यायिक प्रणाली से जुड़े सभी हितधारक अपनी सोच और कार्य संस्कृति में आवश्यक बदलाव लाएंगे और संवेदनशील बनेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने से लेकर अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ाने तक, न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर निरंतर प्रयास करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और बजट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने से हमारी न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य सरकार के सहयोग से ऐसे सभी क्षेत्रों में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए प्रयागराज के चयन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रयागराज की प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका और शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह इस विधि विश्वविद्यालय के लिए आदर्श स्थान है।

राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय आधारित प्रणाली के नियम को सुदृढ़ बनाने में गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व स्तरीय कानूनी शिक्षा हमारे समाज और देश की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्थव्यवस्था के इस युग में हमारे देश में ज्ञान महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षी नीति कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए प्रारंभ में ही सुविचारित तरीके से सभी पद्धतियों की स्थापना करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जैसे ही प्रणाली स्थापित हो जाती है इसमें सुधार लाने की प्रक्रिया जटिल होती जाती है।

9/11 आतंकी हमले ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया : पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए। दुनिया को झकझोर देने वाले इस दर्दनाक दिन की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि दुनिया अब महसूस कर चुकी है कि 9/11 आतंकी हमले जैसी त्रासदियों का स्थायी समाधान भारत के मानवीय मूल्यों के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने कहा कि 9/11 एक ऐसी तारीख है जिसे मानवता पर हमले के लिए याद किया जाता है और इसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। मोदी अहमदाबाद में सरदारधाम भवन परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। बता दें कि 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसने 2996 लोगों की जान ले ली। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया था। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भूला नहीं है जब रोज़ की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18 हजार कर्मचारी रोजमर्रा का काम निपटाने में जुटे थे, लेकिन सुबह 8:46 मिनट पर कुछ ऐसा हुआ कि अब तक सामान्य सी मालुम पड़ रही यह सुबह खौफनाक हो उठी।

चलती कार में 20 वर्षीय युवती को ड्रग्स देकर 5 लोगों ने किया गैंगरेप

» फिर सड़क पर फेंककर हुए फरार

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु में चेन्नई के निकट कांचीपुरम शहर में चलती कार में पांच लोगों ने एक 20 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप किया। लड़की का बॉयफ्रेंड भी इसमें शामिल था, उसने ही अपने चार अन्य दोस्तों को साथ मिलकर पर पीड़िता के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में बॉयफ्रेंड सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले पीड़िता की दोस्ती गुनासीलन नाम के लड़के से हुई थी। दोनों रोजाना दुकान पर मिलते थे। दोनों की सोशल मीडिया के जरिए भी बात होती थी। गुनासीलन ने अपने एक दोस्त से भी पीड़िता की पहचान कराई थी। दोनों ने युवती से वादा किया था कि वे उसे किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिला देंगे। 8 सितंबर को गुनासीलन पीड़िता को कार से कांचीपुरम में एक फार्म हाउस में ले गया। रास्ते में पीड़िता को सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया गया। जब पीड़िता बेहोश हो गई, तो उसने अपने चार दोस्तों को बुला लिया और कार में ही उसके

साथ गैंगरेप किया।

होश में आने पर पीड़िता ने भागने की कोशिश की और अपने पैरों से कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश की। इसे देखकर स्थानीय लोगों का ध्यान कार की तरफ गया। यह देखकर आरोपी पीड़िता को चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर फेंक कर भाग गए। पीड़िता को कांचीपुरम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि वह ठीक हो रही है।

घटना के सामने आने के तुरंत बाद हरकत में आई पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार और शुक्रवार को एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में एक वकील, एक लॉ यूनिवर्सिटी का छात्र और चाय की दुकान का एक कर्मचारी शामिल है। ये सभी कांचीपुरम के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई टू-प्लस-टू वार्ता

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा एवं विदेश मंत्रालय स्तर के उच्च स्तरीय संवाद की शनिवार को शुरुआत की। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच दोनों देशों के बीच संपूर्ण रक्षा एवं सामरिक सहयोग को और बढ़ाना है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों क्रमश- मारिस पायने और पीटर डटन के साथ यहां पर आरंभिक टू-प्लस-टू वार्ता की। यह संवाद ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान में हालात पर है और इस वार्ता के दौरान भी इसपर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री डटन के साथ शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की वहीं जयशंकर ने विदेश मंत्री पायने से टू-प्लस-टू वार्ता से ठीक पहले मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने वार्ता में अफगानिस्तान में नाजुक सुरक्षा हालात पर चर्चा की और तालिबान शासित अफगानिस्तान से आतंकवाद फैलने की आशंका से संबंधित साझा चिंताओं के बारे में बात की। विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता ऐसे समय हो रही है जब क्वाड समूह के सदस्य देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। इस समूह में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और जापान भी हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम

को संबोधित करते हुए पायने ने शुक्रवार को कहा कि क्वाड तेजी से और बहुत प्रभावी रूप से उभरा है और ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में एक मजबूत नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना करता है। पायने ने हिंद-प्रशांत के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में बात की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा क्षेत्र चाहता है जहां बड़े और छोटे देशों के अधिकारों का सम्मान किया जाए तथा कोई भी एकल प्रभावशाली शक्ति दूसरों के लिए परिणाम तय नहीं करे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ा है। पिछले साल जून में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के दौरान साजो- समान की सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी वर्चुअल विवाह पंजीकरण की अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाह पंजीकरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आभासी उपस्थिति का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा कि अब वेब पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगभग आदर्श बन गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टियों की आभासी उपस्थिति में विवाह को पंजीकृत किया जा सकता है और वर्तमान समय में नागरिकों को कानून की कठोर व्याख्या के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है, जो व्यक्तिगत उपस्थिति का आह्वान करता है।

जस्टिस रेखा पल्ली ने अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय जोड़े की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां शादी का पंजीकरण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शारीरिक उपस्थिति को अनिवार्य आवश्यकता नहीं मानने से पक्षकारों को आसानी से अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जस्टिस पल्ली ने 9 सितंबर को अपने आदेश में कहा कि मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि पंजीकरण आदेश के खंड 4 में व्यक्तिगत उपस्थिति शब्द को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षित उपस्थिति को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा

» कहा- संगठन के लिए करेंगे काम

गांधीनगर (आरएनएस)। गुजरात में आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। यहां राजभवन में अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौपने के बाद रूपाणी ने पत्रकारों कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है। अब वह पार्टी में जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी उसे निभायेंगे। दो बार मुख्यमंत्री रहे रूपाणी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और जनता का आभार भी प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब वह संगठन के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुझे लगातार सहयोग मिला है। रुपाणी ने कहा कि मेरे इस्तीफे से किसी नए नेता को इस जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी गई थी और यह भी मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगला चुनाव पूरी दमखम के साथ लड़ेगी और चुनाव में जीत भी दर्ज करेगी। रुपाणी ने कहा कि मुझे इस जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी अलग-अलग वक्त में जिम्मेदारियां बदलती रहती है और इसी कड़ी में मेरा इस्तीफा हुआ है। सभी लोग एकगुट होकर गुजरात के विकास के लिए काम करेंगे। ज्ञातव्य है कि अगले साल ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। रूपाणी के इस्तीफ़े को इससे जुड़ी सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी रणनीति से जोड़ कर देखा जा रहा है। इस बीच, रूपाणी के उत्तराधिकारी को अब तक घोषित नहीं किया गया है। रूपाणी ने आज सुबह ही एक कार्यक्रम में शिरकत की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विडीओ कानफ्रेंसिंग के ज़रिए सम्बोधन किया था।

देश में दूसरे दिन कोरोना मामलों में मामूली गिरावट

» 24 घंटे में 33,376 नए मामले, 308 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। केरल और महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच पिछले 24 घंटे में 33,376 नए मामले दर्ज किये गये। वहीं इस दौरान 308 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत भी हुई। जबकि 32,198 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में शनिवार को बीते 24 घंटे में 33,376 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश में अब तक 3.32 करोड़ से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। जबकि अब तक इस भयानक बीमारी के संक्रमण से 4.42 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 32,198 रही। इस प्रकार देश में कोरोना की जंग जीतने वालों की संख्या बढ़कर 3,23,74,497 हो गई है। जबकि देश में सक्रीय मरीजों की संख्या कम होकर 3,91,516 रह गई है। अब तक 73 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लग चुकी है। कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो रिकवरी रेट अब भी चिंता वाली ही है, क्योंकि रोजाना मिलने वाले केसों की संख्या अब भी ठीक होने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना का 65.27 लाख टीकाकरण हुआ। अब तक देश में 73.05 करोड़ लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है।

केरल में मामूली कमी- इधर केरल में कोरोना के मामलों में मामूली कमी देखी गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में 25 हजार नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 177 लोगों की मौत हुई है। केरल में कोरोना के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में कोरोना की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन केरल अब भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 33 हजार नए मरीजों में से केरल से ही 25 हजार नए संक्रमित सामने आ रहे हैं।

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।